गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 243
दि. 03.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

छोटे शहरों के सर्वांगीण विकास से 'विकसित गुजरात@2047' के विजन की ओर लंबी छलांग

राज्य में 5 सैटेलाइट टाउन के मास्टर प्लान बनाने के लिए अर्बन प्लानर्स को आमंत्रण

(जीएनएस)। गांधीनगर, 02 जनवरी : वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा भारत के सभी राज्यो के सर्वांगीण विकास को वेग देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टियर-2 व टियर-3 शहरों के रणनीतिक विकास को गति देने का विजन प्रस्तुत किया है। इस विजन के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अक्टूबर-2025 में पाँच सैटेलाइट टाउन विकसित करने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के क्रियान्वयन के हिस्से के रूप में अब इन शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अर्बन प्लानर्स को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए टेंडर द्वारा अर्बन प्लानर्स की नियुक्ति करने का कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 2030 तक इन शहरों में महानगरों जैसी सुविधाएँ विकसित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का आयोजन है, जिससे बड़े शहरों पर बोझ को घटाया जा सके। शहरी विकास वर्ष-2025 में 'अर्निंग वेल-लिविंग वेल' का मंत्र साकार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अहमदाबाद के पास साणंद, वडोदरा के पास सावली, गांधीनगर के पास कलोल, सूरत के पास बारडोली तथा राजकोट के पास हीरासर को 'सैटेलाइट टाउन' के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव करके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्राप्त अर्बन प्लानर्स को मास्टर प्लान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया है। आगामी दो महीनों में कन्सल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी, जो एक वर्ष के भीतर इन शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करके प्रस्तुत करेंगे।

▸▸ 2030 तक साणंद, कलोल, सावली, बारडोली तथा हीरासर को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा

▸▸ अर्बन एरिया देश का ग्रोथ सेंटर है, विकसित भारत के निर्माण के लिए शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाना होगा : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

क्या है सैटेलाइट टाउन ?

सैटेलाइट टाउन यानी बड़े शहर या महानगर के निकट स्थित ऐसा शहर, जहाँ बड़े शहर से एक घण्टे में पहुँचा जा सकता है। ऐसे शहरों की पहचान कर उन्हें आर्थिक रूप से व्यस्त गतिविधियों का केन्द्र बनाने का उद्देश्य है, जिससे बड़े शहरों पर बोझ घटे और इन शहरों में रोजगार के अवसर के द्वार खुलें। इन शहरों में विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा नागरिक केन्द्रित सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

गुजरात के पाँच सैटेलाइट टाउन

राज्य सरकार ने प्रारंभिक चरण में अहमदाबाद के पास साणंद, वडोदरा के पास सावली, गांधीनगर के पास कलोल, सूरत के पास बारडोली तथा राजकोट के पास हीरासर को 'सैटेलाइट टाउन' के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। इन पाँच शहरों में मास्टर टाउन प्लानिंग के साथ परिवहन, उद्योगों, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

सैटेलाइट टाउन में विकसित होने वाली सुविधाएँ

सैटेलाइट टाउन में अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन सुविधा (इलेक्ट्रिक बस सुविधा सहित), जलापूर्ति तथा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिंग रोड, अर्बन फॉरेस्ट पार्क, सुंदर तालाब, मॉडल फायर स्टेशन तथा मिक्स यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर (ऑफिस, घर, दुकानें; सब नजदीक में) का निर्माण किया जाएगा। इन सुविधाओं का कार्य तेजी से शुरू करने के लिए मंजूरी तथा निगरानी समिति का गठन किया गया है।

अर्बन एरिया देश का ग्रोथ सेंटर है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

शहरी विकास के विजन को प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है, "अर्बन एरिया देश का ग्रोथ सेंटर है, तब विकसित भारत के निर्माण के लिए शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाना चाहिए और टारगेट निर्धारित कर उस अनुसार नए उत्पादनों तथा क्वॉलिटी वर्क पर कार्य कर विकास साधना चाहिए। आज देश में दो लाख से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश स्टार्टअप टियर-2 व टियर-3 शहरों में स्थित हैं। इनमें अनेक स्टार्टअप का नेतृत्व बेटियाँ कर रही हैं। इतना ही नहीं; इन शहरों के बच्चे शिक्षा के अलावा अन्य अनेक गतिविधियों में भी अपेक्षाकृत आगे हैं। इसलिए ऐसे छोटे शहरों में विकास की अनेक क्षमताएँ विद्यमान हैं।"

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पांच माह की कैद समाप्त होने का रास्ता साफ

(जीएनएस)। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) से संबंधित मामलों में उन्हें जमानत दे दी। इस फैसले के साथ ही करीब पांच माह से अधिक समय से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद चैतन्य बघेल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बन गया है।

हाईकोर्ट की एकलपीठ के न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इससे पहले अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुनाए जाने के साथ ही चैतन्य बघेल की लगभग 168 दिनों की न्यायिक हिरासत समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है, जिनमें वर्तमान में आदेश दिया गया है, और अन्य प्रकरणों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी रह सकती है।

चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को उनके भिलाई स्थित निवास से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और बाद में सितंबर माह में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भी एक अन्य मामले में औपचारिक गिरफ्तारी की थी, जबकि वे पहले से जेल में बंद थे। इसके बाद से लगातार उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। रायपुर सेंट्रल जेल में बिताए गए इन महीनों के दौरान यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील बना रहा।

जांच एजेंसियों ने इस मामले में चैतन्य बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी और एसीबी का दावा है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के जरिए राज्य को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एजेंसियों के अनुसार, इस पूरे सिंडिकेट में चैतन्य बघेल की भूमिका अहम रही और उन्होंने करीब 1,000 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन को सीधे तौर पर संभाला। एसीबी का यह भी आरोप है कि इस घोटाले से उन्हें व्यक्तिगत रूप से 200 से 250 करोड़ रुपये का लाभ मिला। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पूरे कथित घोटाले का आकार 3,200 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जा रहा है, जिसे राज्य के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक अपराधों में से एक माना जा रहा है।

वहीं बचाव पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत में कहा कि चैतन्य बघेल को बिना ठोस सबूतों के केवल एक सह-आरोपी के बयान के आधार पर फंसाया गया है। बचाव पक्ष का तर्क था कि न तो उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश किया गया और न ही यह साबित किया गया कि उन्होंने कथित अपराध से कोई सीधा लाभ उठाया। वकीलों ने यह भी दलील दी कि जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी से पहले चैतन्य बघेल का औपचारिक बयान तक दर्ज नहीं किया और उन्होंने जांच में सहयोग करने से कभी इनकार नहीं किया। इसके अलावा, लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया।

हाईकोर्ट ने जमानत देते समय इस बात को ध्यान में रखा कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं, जांच का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और फिलहाल उनके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई ठोस आशंका सामने नहीं आई है। अदालत ने यह भी माना कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, खासकर तब जब ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना हो।

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है और कानून अपना काम करेगा। फिलहाल, चैतन्य बघेल की रिहाई को लेकर सभी निगाहें जेल प्रशासन और निचली अदालतों की औपचारिक प्रक्रियाओं पर टिकी हुई हैं, जिनके पूरा होते ही वे जेल से बाहर आ सकेंगे।

शराब पीकर उड़ान से पहले पकड़ा गया पायलट, एयर इंडिया ने मांगी माफी; डीजीसीए ने किया स्पष्टीकरण

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कनाडा से भारत आ रही एयर इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से जुड़े पायलट के शराब सेवन के मामले पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यात्रियों से माफी एयर इंडिया ने मांगी थी, न कि डीजीसीए ने। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि इस प्रकरण को लेकर डीजीसीए ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, जिसे अब नियामक संस्था ने सिरे से खारिज कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह घटना 23 दिसंबर की है, जब वैंकूवर से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-186 के पायलट पर उड़ान से पहले शराब सेवन का संदेह जताया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत कनाडाई अधिकारियों ने पायलट का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया, जिसमें वह फेल पाया गया। इसके बाद तत्काल प्रभाव से पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया और विमान संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिससे उड़ान में देरी हुई।

इस घटना के बाद यात्रियों को हुई असुविधा को लेकर एयर इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए माफी जारी की। एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कंपनी की 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' है और इसी के तहत संबंधित पायलट के खिलाफ कार्रवाई की गई।

डीजीसीए ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उसने इस मामले में केवल नियामकीय भूमिका निभाई है। पायलट को तुरंत उड़ान के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया और औपचारिक जांच शुरू की गई। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि उसने यात्रियों से कोई माफी जारी नहीं की, बल्कि यह पूरी तरह से एयर इंडिया का निर्णय था। नियामक संस्था ने यह भी दोहराया कि विमानन सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जांच पूरी होने तक संबंधित पायलट को उड़ान संचालन से दूर रखा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एयरलाइन और डीजीसीए दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

डीजीसीए ने साथ ही उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें यह कहा गया था कि नियामक संस्था ने इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। नियामक के अनुसार, उसकी भूमिका नियमों का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यक कार्रवाई करने तक सीमित है, जबकि यात्रियों से संवाद और माफी की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइन की होती है।

महंगाई की आग में झुलसा ईरान, कोम में फायरिंग से तीन की मौत; खामेनेई शासन के खिलाफ देशभर में उबाल

(जीएनएस)। तेहरान। ईरान में महंगाई, गिरती मुद्रा और बदहाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ जनाक्रोश अब देशव्यापी अशांति में बदल गया है। लगातार पांचवें दिन जारी प्रदर्शनों के दौरान पवित्र शहर कोम में सुरक्षा बलों की फायरिंग में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ विरोध अब ईरान के बड़े हिस्से में फैल चुका है, जिससे शासन की चिंता बढ़ गई है।

कोम, जिसे शिया धर्मगुरुओं और इस्लामिक गणराज्य की वैचारिक रीढ़ माना जाता है, वहां खुले तौर पर शासन विरोधी नारे लगना बीते पांच दशकों में एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंधों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब भीड़ को तितर-बितर करने में सुरक्षा बल नाकाम रहे तो उन्होंने गोलीबारी की, जिससे स्थिति और विस्फोटक हो गई। कोम में हुए इस घटनाक्रम ने पूरे देश में आक्रोश की लहर को और तेज कर दिया है।

तेहरान, मशहद, इस्फ़हान, लोरेस्टान और खुज़ेस्तान सहित कई प्रांतों में रातभर विरोध प्रदर्शन होते रहे। फूलदशहर, कुहदाश्त, लोरदेगान और अन्य छोटे शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जबकि कुछ इलाकों में सीधी गोलीबारी की भी खबरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, न्यायालयों, बैंकों और शुक्रवार की नमाज से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया, जिसे शासन के प्रति बढ़ते गुस्से का प्रतीक माना जा रहा है।

स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं। कुर्द अधिकार समूह हेंगाओ और अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। तेहरान में गिरफ्तार की गई छह महिलाओं को कुख्यात एविन जेल के महिला वार्ड में रखा गया है, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं।

ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुद्रा रियाल की लगातार गिरती कीमत, आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों का बोझ आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में तेज़ उछाल ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक दबाव ने राजनीतिक असंतोष को इस स्तर तक पहुंचा दिया है कि अब पवित्र शहरों में भी शासन के खिलाफ खुली आवाज़ें उठने लगी हैं।

कोम में "यह आखिरी लड़ाई है" और "तानाशाह मुर्दाबाद" जैसे नारे गूंजना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विरोध केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सीधे सत्ता के खिलाफ राजनीतिक रूप ले लिया है। अब यह संकट किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। सवाल यह है कि ईरानी शासन सख्ती के जरिए हालात पर काबू पाएगा या जनता का यह गुस्सा किसी बड़े राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ेगा।

साजिश नाकाम: श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी ड्रोन गिरा, 4.88 किलो हेरोइन जब्त; तीन तस्कर गिरफ्तार

(जीएनएस)। श्रीगंगानगर। राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए की जा रही मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नए साल की रात सीमा पार से भेजी गई करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन गिराने के दौरान तकनीकी खराबी के कारण ड्रोन क्रैश हो गया। सतर्क गश्त पर तैनात पुलिस ने मौके से 4.88 किलो हेरोइन, एक अत्याधुनिक ड्रोन और तीन तस्करों को गिरफ्तार कर इस साजिश को नाकाम कर दिया।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई रावला थाना क्षेत्र में 15 केएनडी पुलिया के पास नहर किनारे की गई। एक जनवरी की रात नियमित गश्त के दौरान पुलिस टीम ने तीन युवकों को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा। पुलिस वाहन को देखते ही तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास से कुल 4 किलो 880 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। इसके साथ ही एक डीजेआई कंपनी का ड्रोन भी जब्त किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भारत भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि ड्रग्स गिराते समय ड्रोन में तकनीकी खराबी आ गई और वह नीचे गिर पड़ा, जिससे तस्करों की योजना विफल हो गई।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जगनदीप सिंह उर्फ लब्बू सिंह (26) निवासी चक 10 के, अनूपगढ़; नीटू सिंह उर्फ रवनीत सिंह (21) निवासी डबली राठान, हनुमानगढ़; और सतपाल सिंह (27) निवासी चक 04 एसटीआर, घड़साना के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जगनदीप सिंह के पास से 1019 ग्राम, नीटू सिंह के पास से 2048 ग्राम और सतपाल सिंह के पास से 1021 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जबकि ड्रोन सतपाल के बैग से मिला।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहान ने बताया कि तीनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि पाकिस्तान से जुड़े कौन से गिरोह इस तस्करी के पीछे सक्रिय हैं और भारत में इनके स्थानीय संपर्क कौन-कौन हैं।

बीएसएफ के सहयोग से सीमा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी के मामलों में हाल के वर्षों में तेजी आई है, जिसे देखते हुए सीमा पर निगरानी और चौकसी और अधिक सख्त कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुटी हुई हैं।

गरवी गुजरात हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2002

Jio Air Fiber · Jio Tv + · Jio Fiber · Daily Hunt · ebaba Tv · Dish Plus

DTH live OTT · Rock TV · Airtel · Amezone Fire · Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

मेहनतकशों की बेकद्री

बाजार आने-जाने के झंझट से बचा लोगों के घरों में तुरत-फुरत जीवन उपयोगी सामान पहुंचाने वाले गिग-वर्कर्स की जटिल कार्यपरिस्थितियां और पसीने का मोल न मिलना, बेहद चिंता की बात है। अपना व परिवार का पोषण करने वाले ये युवा अकसर सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाते और सीढ़ियां चढ़कर ऊंची मंजिलों में दरवाजों तक सामान पहुंचाते देखे जा सकते हैं। बेहद कम मेहनताने, कंपनी मालिकों के दबाव व ग्राहकों की उपेक्षा झेलते गिग वर्कर्स ने नये साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल करके अपनी बदहाली को ही उजागर किया है। संवेदनशील कार्य परिस्थितियों और नौकरी की असुरक्षा के चलते गिग-वर्कर्स हड़ताल पर थे। हालांकि, नये साल पर काम के दबाव व पूरी तरह संगठित न होने के कारण इनकी हड़ताल का कुछ ही इलाकों में असर देखा गया। पूरे देश में सामान की आपूर्ति बाधित हुई हो, ऐसा भी कोई समाचार नहीं मिला है। लेकिन गिग-वर्कर्स की विषम कार्य-परिस्थितियों की ओर पूरे देश का ध्यान जरूर गया है। पिछले दिनों आप के राघव चड्ढा और राजद के मनोज कुमार झा जैसे सांसदों ने गिग वर्कर्स के शोषण का मुद्दा संसद में उठाया था। निस्संदेह, देश की गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन में अपनी क्षमता साबित की है। विडंबना है कि भारत युवाओं को देश का कहा जाता है, लेकिन हम उनकी आकांक्षाओं का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल, गिग-वर्कर्स की प्रमुख मांग है कि उनके काम का बेहतर भुगतान हो और उनके लिये बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनायी जाएं। उनकी इस हड़ताल ने इन मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा है। लेकिन देश के प्रमुख खाद्य वितरण करने वाली कंपनी ने 31 दिसंबर को इस हड़ताल के बावजूद ऑर्डर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। वहीं थके-हारे बाइकर्स अपनी अनगिनत शिकायतें व्यक्त करते रहे। दरअसल, विडंबना यह है कि खूब काम लेने के बावजूद गिग-वर्कर्स को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी के दायरे से बाहर आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। दरअसल, गिग-वर्कर्स को नई अर्थव्यवस्था में नियोक्ता एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के दायित्व से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन नियोक्ताओं की हायर व फायर की रणनीति के चलते, वे असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में काम करने को बाध्य होते हैं। इसके बावजूद वे आज शहरी जीवन व्यवस्था के लिये अभिन्न अंग बन गए हैं। लोगों की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दौड़ते रहते हैं। वे सामान दस मिनट तक दरवाजे पर पहुंचाने के दबाव में हांफते-भागते, मोटरसाइकिल दौड़ाते और सीढ़ियों पर सामान चढ़ाते अकसर नजर आते हैं। आम तौर पर उपभोक्ताओं का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। देरी होने पर इन्हें झिड़का जाता है। सामान में नुक्स निकालकर इन्हें दौड़ाया जाता है। आज भारत में इनकी संख्या सवा करोड़ से अधिक है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इन कामगारों की संख्या दो करोड़ पैंतीस लाख तक हो सकती है। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि मेहनताने में कटौती, जरा सी चूक पर आर्थिक दंड तथा समय से पहले पहुंचाने के दबाव से गिग-वर्कर्स त्रस्त हैं। मुश्किल परिस्थितियों में काम करते रहने के बावजूद ये कामगार हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग नहीं ले पाये। दरअसल, प्लेटफॉर्म अकसर प्रोत्साहन और अतिरिक्त वेतन के जरिये श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को दबा देते हैं। निश्चित रूप से गिग-वर्कर्स का लगातार 14 घंटे काम करने के बावजूद सात-आठ सौ रुपये कमाना और दुर्घटना बीमा से वंचित रखना, इस व्यवस्था की उन खामियों की ओर भी इशारा करता है, जिन्हें केवल फौरी लालच या प्रोत्साहन से ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में हालिया श्रम सुधारों का महत्व बढ़ जता है। जिसमें पहली बार, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानून के तरह औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर के टर्नओवर का एक से दो फीसदी सामाजिक सुरक्षा कोष में अनिवार्य योगदान और आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर को कानूनी मान्यता की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव का संकेत देते हैं। हालांकि, कार्यान्वयन ही यह निर्धारित करेगा कि ये सुधार परिवर्तनकारी साबित होते हैं या केवल प्रतीकात्मक रहते हैं।

आपदाओं से उबरने की क्षमता में वृद्धि जरूरी

> “जलवायु बदलाव के चलते मध्य हिमालय क्षेत्र में मौसमी अतिरेक से आपदाएं बार-बार आ रही हैं। जिससे प्रकृति, बुनियादी ढांचा व मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। इससे जल्द उबरने को क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

गर्म होती धरा, उससे उपजते वैश्विक जलवायु बदलाव व आपदाएं आकस्मिक व अतिशय घातक होते जा रहे हैं। कृषि, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण संरचना जैसे क्षेत्रों में इनका प्रतिगामी असर जैविक व भौतिक दोनों पर पड़ा है। इससे बना-बनाया ध्वस्त भी हो जाता है। फिर से सब कुछ सहेजना मुश्किल होता है। आकस्मिक आपदाओं की निरंतरता के बीच हर क्षेत्र में क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने का मुद्दा केन्द्र में आ गया है।

मध्य हिमालय में जलवायु बदलाव के दो-तीन बड़े असर जाड़ों में भी वनों में आग, बादल विस्फोट, ग्लेशियर टूटने, ग्लेशियर झीलें बनने व ग्लेशियर पीछे खिसकने तथा अपनी मोटाई खोने के रूप में दिखते हैं। हिमस्खलन, भूस्खलन व दावानल की घटनायें बढ़ी हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष भी बढ़े हैं।

सालों से ऐसा हो रहा है कि एक आपदा के बाद संभल नहीं पाते, दूसरी आ जाती है। उत्तराखंड 2025 में भी भारी आपदाग्रस्त रहा। इनसे हुई क्षति की आपूर्ति तो दूर की बात, अभी कहीं-कहीं बीते दशक की आपदाओं में क्षतिग्रस्त कई पुल व सड़कें भी अब तक नहीं बनाई जा सकी हैं। जरूरी है जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य हो। उत्तराखंड व हिमाचल जैसे राज्यों को क्लाइमेट रेजिलियंस पर काम करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देहरादून में बीते 13 व 14 अक्तूबर को ‘उत्तराखंड में जलवायु बदलाव रेजिलियंस पर मिलजुल कर कार्यवाही - राष्ट्रीय विचार विमर्श’ आयोजित किया गया था। सहमति के बिंदुओं पर आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। क्लाइमेट रेजिलियंस किसी भी प्रणाली व जैविक-अजैविक एकांशों की वह क्षमता है जिससे जलवायु बदलाव प्रेरित अतिवृष्टि,अतिताप, अतिशीत अति बवंडर

व समुद्री तूफानों की घटनाओं के आघातों-व्यवधानों से उबरकर वह पहले जैसी भूमिका निर्वहन में सक्षम हो जाता है।

विकास की निरंतरता के लिये खेती, जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, सड़कों, परिवहन, भवन, पुल, संचार, स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे क्लाइमेट रेजिलियंट होने चाहिये। खेती क्लाइमेट रेजिलियंट होगी तो किसान की आय व खाद्य सुरक्षा में अनिश्चितता कम होगी। सीवरेज व पेयजल व्यवस्था क्लाइमेट रेजिलियंट होंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी। ऐसी ही समस्या है सेनिटेशन सततता की। अतिशय बारिश, भूस्खलन, बाढ़ व सूखे जैसी जलवायु आपदायें सेनिटेशन प्रणालियों पर गंभीर असर डाल रही हैं। ऐसे में शौचमुक्त क्षेत्रों में फिर खुले में शौच होना शुरू हो जाता है। आपदाओं में शौचालय प्रणालियों को अबाधित बनाये रखने के लिये यूनीसेफ अपने वाश स्टाफ को जलवायु बदलाव अनुकूलन रणनीति पर प्रशिक्षण दे रहा है।

आजकल ई-गवर्नेंस व ई-बैंकिंग के साथ उद्योग, व्यवसाय, बैंकिंग व प्रशासकीय व्यवस्थाएं जुड़ी हैं तो क्लाइमेट रेजिलियंसी के मानक ये भी हैं कि बाढ़ आदि आपदा में यदि डाटा क्षतिग्रस्त हो जाएं तो उसकी रिकवरी यथाशीघ्र हो जाये।

क्लाइमेट रेजिलियंस आपदा के बाद की स्थिति का विवेचन है। आघात से उबरने में लगने वाले समय का आकलन है। यदि हम प्रोएक्टिव हों तो पूर्व चेतावनियों से आपदाओं के जोखिम कम कर सकते हैं जैसे बाढ़ या चक्रवाती तूफानों में लोगों को तटों से हटा सकते हैं। ग्लेशियर टूटने या उनमें झील बनने की संभावनाओं की मॉनिटरिंग संभव है।

प्रकृति पर भी जलवायु बदलाव से ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी अतिरेकों व अनिश्चितताओं के कुप्रभाव कम नहीं हैं। प्राकृतिक घटकों की रेजिलियंस पर भी फोकस की जरूरत है। प्रकृति की मदद करेंगे तो प्रकृति क्लाइमेट रेजिलियंस पाने में मदद करेगी। किन्तु पूरे विश्व में ही प्राकृतिक संसाधनों की रेजिलियंस में मानवीय कृत्यों से कमी आई है। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बड़े-छोटे बांध बनाकर अथवा सुरंगों में डाल कर उनके फ्लड प्लेनों पर निर्माण व अन्य अतिक्रमण कर उनके बहावों व फैलावों से नदियों को मिलने वाली रेजिलियंस क्षीण की। बेतरतीब कटान से पहाड़ी ढलानों से भूस्खलनों के जोखिम बढ़ाये। ग्लेशियरों की रेजिलियंस खत्म की उनके निकट तक भारी निर्माण व सड़क बनाकर। वहीं वायु मार्ग में भारी ट्रैफिक के प्रदूषण व कम्पन से। वनों की रेजिलियंस खत्म की आग, प्रदूषण, वन कटान से। जमीन की रेजिलियंस कम की ढलान खत्म करके। खेती की रेजिलियंस नष्ट की लैब निर्मित बीजों व रासायनिक खादों से। क्लाइमेट रेजिलियंस विधिक, पर्यावरणीय व लैंगिक न्याय से भी जुड़ा विषय है क्योंकि जिनकी आपदा लाने में ना के बराबर भूमिका होती है वे भी इसका दंश झेलते हैं। यह अन्याय ही तो है कि उत्तराखंड के ग्रामीणों की गुहारों को नजरअंदाज किया। मसलन- उनके गांवों के नीचे सड़क या टनल बनाने के लिए बारूद विस्फोट न करें, उनके पुल के नीचे अवैध खनन न करें, उनके गांवों के ऊपर से सड़क कटानों का मलबा नीचे न फेंकें, समीपस्थ बांधों व जलाशयों में अत्यधिक पानी न भरें। इन सब कारणों से सुशासन जरूरी है। ताकि आपदा में टूटे पुल, सड़क स्कूल, अस्पतालों को बनने में सालों साल न लगें। क्लाइमेट रेजिलियंस पाने के लिये प्रभावित व्यक्ति या समुदाय की खुद को उबारने व मनोवैज्ञानिक आघातों से बाहर निकलने की मजबूत इच्छाशक्ति भी जरूरी है।

प्रेरणा

महान बनने की शुरुआत: व्यक्तित्व में छिपी प्रतिभा को पहचानने की दृष्टि

इतिहास केवल तिथियों और युद्धों का संकलन नहीं है, बल्कि वह उन व्यक्तित्वों की गाथा है जिनमें साधारण जीवन के बीच असाधारण संभावनाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों को समय से पहले पहचान लेने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। आचार्य चाणक्य उन विरले महापुरुषों में थे, जिनकी दृष्टि बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन और व्यवहार से उसके भविष्य को पढ़ लेती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रसंग इसी सत्य को उजागर करता है कि प्रतिभा का जन्म राजमहलों में ही नहीं, जंगलों, गलियों और संघर्षों के बीच भी हो सकता है।

चंद्रगुप्त का बाल्यकाल अभावों और अनिश्चितताओं से भरा था। न राजसी संरक्षण, न सत्ता का सहारा। फिर भी उसके व्यक्तित्व में कहीं भी हीनता या भय नहीं था। यही वह पहली विशेषता थी, जिसने चाणक्य का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। सामान्यतः कठिन परिस्थितियों में पले बच्चे या तो अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं या भीतर से टूट जाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त इन दोनों से अलग था। उसमें परिस्थितियों को देखने, समझने और उनके भीतर अपनी भूमिका खोजने की क्षमता थी।

जिस दृश्य का उल्लेख इतिहास करता है, वह अत्यंत साधारण है—जंगल में बच्चों का राजा-प्रजा का खेल। परंतु इसी साधारण दृश्य में असाधारण संकेत छिपे थे। खेल के दौरान चंद्रगुप्त केवल राजा की भूमिका निभा नहीं रहा था, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से नेतृत्व कर रहा था। उसके निर्णयों में अनुशासन था, आदेशों में स्पष्टता और व्यवहार में संतुलन। वह दूसरों को डराकर नहीं, बल्कि स्वीकार्यता के साथ नेतृत्व कर रहा था। यही गुण किसी भी सच्चे शासक की पहचान होते हैं।

प्रतिभा का एक बड़ा चिन्ह यह है कि व्यक्ति कल्पना और वास्तविकता के बीच सेतु बना लेता है। चंद्रगुप्त का खेल केवल कल्पना नहीं था, वह उसकी आंतरिक आकांक्षा का प्रतिबिंब था। वह अपने मन में स्वयं को सीमाओं में बंधा हुआ नहीं देखता था। उसके भीतर विस्तार की भावना थी—कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की। चाणक्य जैसे अनुभवी मनीषी ने इसी विस्तार चेतना को पहचान लिया।

आचार्य चाणक्य की दृष्टि का महत्व यहां समझ में आता है। वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव के गहरे अध्येता भी थे। उनके लिए प्रतिभा का अर्थ केवल बुद्धि की तीव्रता नहीं था, बल्कि चरित्र की दृढ़ता, सीखने की इच्छा और आत्मसंयम भी था। चंद्रगुप्त में ये सभी गुण बाल्यावस्था में ही दिखाई देने लगे थे। वह प्रश्न पूछता था, उत्तर खोजता था और अपने अनुभवों से सीखने की कोशिश करता था।

एक अन्य महत्वपूर्ण चिन्ह जो चंद्रगुप्त में स्पष्ट था, वह था भय का अभाव। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जोखिमों से अनजान था, बल्कि वह जोखिमों से भागता नहीं था। भयमुक्त होना किसी भी नेता के लिए आवश्यक है, क्योंकि डर निर्णयों को कमजोर बना देता है। चंद्रगुप्त का आत्मविश्वास परिस्थितियों से नहीं, बल्कि स्वयं की क्षमता पर विश्वास से उपजा था। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उसे विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए तैयार करता है।

प्रतिभा का संबंध केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं होता, बल्कि सामूहिक हित की भावना से भी होता है। चंद्रगुप्त के खेल में भी यह झलकता था कि वह न्याय और व्यवस्था को महत्व देता है। वह केवल राजा बनकर आदेश नहीं देता था, बल्कि प्रजा की भूमिका निभाने वालों की बात भी सुनता था। यह गुण आगे चलकर उसे एक ऐसा शासक बनाता है, जो केवल सत्ता नहीं चलाता, बल्कि समाज को संगठित करता है।

इस प्रसंग से एक गहरा सामाजिक संदेश भी निकलता है। आज के समय में हम प्रतिभा को अंकों, परीक्षाओं और उपलब्धियों के तराजू पर तौलते हैं। हम भूल जाते हैं कि नेतृत्व, दूरदृष्टि और संतुलन जैसे गुण किसी मार्कशीट में नहीं लिखे जा सकते। चंद्रगुप्त यदि आज के समय में होते, तो संभव है कि उनकी प्रतिभा किसी प्रतियोगी परीक्षा में तुरंत न पहचानी जाती, लेकिन इतिहास गवाह है कि वही बालक आगे चलकर अखंड भारत का स्वप्न साकार करता है।

यह कथा गुरु और शिष्य के संबंध की महत्ता को भी रेखांकित करती है। प्रतिभा अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, उसे सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक भी चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर उसे जागृत किया। यह मार्गदर्शन ही था, जिसने एक साधारण बालक को असाधारण सम्राट में रूपांतरित कर दिया।

अंततः चंद्रगुप्त और चाणक्य की यह कथा हमें यह सिखाती है कि महानता किसी विशेष वर्ग या जन्म की बपौती नहीं है। प्रतिभा के चिन्ह हर समाज, हर परिस्थिति में मौजूद होते हैं। आवश्यकता है उन्हें पहचानने वाली दृष्टि की—चाहे वह किसी गुरु की हो या स्वयं व्यक्ति की। जब मनुष्य अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान लेता है, तब परिस्थितियां स्वयं उसके मार्ग में बदलने लगती हैं।

इतिहास इसलिए प्रेरणा देता है, क्योंकि वह बताता है कि सीमाओं में जन्मा व्यक्ति भी असीम बन सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण है कि जो अपने भीतर सम्राट की सोच पाल लेता है, वही एक दिन इतिहास में अपना नाम अंकित करता है।

उमर खालिद के समर्थन में उतर कर जोहरान मामदानी ने बड़ा खतरनाक खेल खेला है

न्यूयार्क के मेयर जोहरान मामदानी की ओर से भारत में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को भेजे गए एक पत्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि यह पत्र उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात के दौरान दिया गया और इसमें मामदानी ने खालिद के विचारों की तारीफ करते हुए लिखा कि वे उनके बारे में सोच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई चल रही है। इस पत्र के सामने आने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आलोचकों का कहना है कि किसी विदेशी शहर के मेयर द्वारा भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। खासकर तब, जब मामला दंगों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। हम आपको याद दिला दें कि उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आरोप हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में किसी विदेशी जनप्रतिनिधि की ओर से सहानुभूति और प्रशंसा का सार्वजनिक संकेत कई सवाल खड़े करता है।

हम आपको बता दें कि मामदानी के पत्र को सिर्फ एक व्यक्तिगत संदेश नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में भी इस कदम को असहज माना गया है। भारत में यह तर्क उभरा है कि यदि हर देश का स्थानीय नेता दूसरे देश के न्यायिक मामलों पर टिप्पणी करने लगे तो संप्रभुता और संस्थागत सम्मान पर आंच आएगी। देखा जाये तो जोहरान मामदानी का यह कदम साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल है। सवाल सीधा है। सवाल उठता है कि न्यूयार्क के मेयर को यह अधिकार किसने दिया कि वह भारत के दंगों से जुड़े एक आरोपी की तारीफ करे और उसे नैतिक समर्थन दे। मामदानी को समझना होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था सक्षम है, संवैधानिक है और अपने फैसले खुद लेने में समर्थ है। उमर खालिद कोई साधारण सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को वैश्विक मंच से नैतिक समर्थन देना न केवल भारत के लिए गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक परंपरा को जन्म देता है। इससे यह संदेश जाता है कि दंगों और हिंसा से जुड़े आरोपों को वैचारिक खोल पहनाकर महिमामंडित किया जा सकता है। यह संदेश उन तत्वों के लिए संजीवनी का काम करता है जो अराजकता और टकराव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। मामदानी को यह समझना चाहिए था कि भारत का आंतरिक कानून और व्यवस्था किसी विदेशी राजनेता की राय का मोहताज नहीं। यदि उन्हें मानवाधिकार की इतनी ही चिंता है, तो उन्हें अपने देश में चल रही हिंसा, नस्लीय तनाव और अपराध की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत में न्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पत्रों के जरिये।

इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी गलत असर डाल सकता है। जब वहां के नेता दंगों के आरोपी की तारीफ करते हैं, तो यह वहां मौजूद कट्टर और हिंसक विचारधारा के लोगों का हौसला बढ़ाता है। वे इसे यह कहकर पेश कर सकते हैं कि उनके विचारों को वैश्विक मान्यता मिल रही है। यह लोकतंत्र के लिए घातक संकेत है। लोकतंत्र का अर्थ कानून का शासन है, न कि आरोपियों का महिमामंडन।

यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र की बुनियाद एक दूसरे की संस्थाओं के सम्मान पर टिकी होती है। जब कोई विदेशी नेता भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है या एक पक्ष को नैतिक ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश करता है, तो यह आपसी विश्वास को चोट पहुंचाता है। यह न तो कूटनीतिक मर्यादा के अनुरूप है और न ही जिम्मेदार राजनीति का उदाहरण।

मामदानी का पत्र उन तमाम भारतीय नागरिकों की भावनाओं का भी अपमान है जिन्होंने दिल्ली दंगों में अपने परिजन खोए, जिनकी दुकाने जलीं और जिनका जीवन तबाह हुआ। उनके लिए दंगे कोई वैचारिक बहस नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे में दंगों के मास्टरमाइंड की तारीफ करना घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि वह लोकतांत्रिक है या न्यायप्रिय। यहां की अदालतें स्वतंत्र हैं और फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं। यदि उमर खालिद निर्दोष है, तो वह अदालत से बरी होगा। यदि दोषी है, तो सजा पाएगा। इसमें किसी विदेशी मेयर के भावनात्मक पत्र की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जोहरान मामदानी का यह कदम गैर जिम्मेदार, दखल देने वाला और भड़काऊ है। भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान तभी संभव है, जब हर देश अपनी सीमाएं पहचाने और दूसरों की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से बचे। यही संतुलन वैश्विक शांति और आपसी सम्मान की असली कसौटी है।

अभियान

खाली बर्तन नहीं, भरा हुआ जीवन: दादी-नानी की परंपराओं में छिपा समृद्धि का मनोविज्ञान

भारतीय घरों में दादी-नानी की कही बातें अक्सर साधारण, कभी-कभी पुरानी और आज की पीढ़ी को अव्यावहारिक लग सकती हैं। लेकिन जब जीवन के अनुभव बढ़ते हैं, तब एहसास होता है कि उनके शब्दों में केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरी जीवन-दृष्टि छिपी होती थी। “बर्तनों को खाली मत रखना”, “नए साल की पहली सुबह खाली बर्तन नहीं दिखने चाहिए” जैसे वाक्य सिर्फ डर या अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं कहे जाते थे, बल्कि इनके पीछे सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण जुड़े होते थे। यह परंपरा हमें अभाव के डर से नहीं, बल्कि पूर्णता के भाव से जीना सिखाती है।

भारतीय संस्कृति में खालीपन को सामान्य स्थिति नहीं माना गया। चाहे वह मन हो, घर हो या रसोई – हर जगह संतुलन और परिपूर्णता को महत्व दिया गया। दादी-नानी के लिए बर्तन केवल उपयोग की वस्तु नहीं थे, वे जीवन के प्रवाह के प्रतीक थे। जिस घर में बर्तन हैं, वहां भोजन है; जहां भोजन है, वहां परिवार है; और जहां परिवार है, वहां जीवन है। ऐसे में खाली बर्तन केवल धातु या मिट्टी का खाली पात्र नहीं, बल्कि जीवन में किसी कमी का संकेत माने जाते थे।

नए साल की पहली सुबह को विशेष महत्व देने के पीछे भी यही सोच थी। वर्ष की शुरुआत को एक प्रतीकात्मक द्वार माना जाता था, जिससे होकर पूरे साल की ऊर्जा प्रवेश करती है। जिस तरह सुबह की शुरुआत जैसी होती है, वैसा ही दिन गुजरता है, उसी तरह साल की पहली सुबह जैसी होती है, वैसा ही साल बीतता है – यह धारणा दादी-नानी की सोच का आधार थी। अगर साल की शुरुआत में ही घर में खाली बर्तन दिखाई दें, तो मन में अनजाने में ही अभाव, चिंता और असंतोष का भाव बैठ सकता है।

दादी-नानी भले ही मनोविज्ञान का नाम न जानती हों, लेकिन वे मन की प्रकृति को भली-भांति समझती थीं। मन दृश्य से प्रभावित होता है। जो आंखें देखती हैं, वही मन स्वीकार करता है। अगर सुबह उठते ही खाली रसोई, उल्टे बर्तन और खाली पात्र दिखें, तो अवचेतन मन उसे “कमी” के संकेत के रूप में ग्रहण करता है। इसके विपरीत, साफ रसोई और भरे हुए बर्तन मन में सुरक्षा, संतोष और स्थिरता का भाव पैदा करते हैं।

हिंदू दर्शन में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। “अन्नं ब्रह्म” का अर्थ यही है कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि जीवन का मूल तत्व है। दादी-नानी अन्न का सम्मान करना जानती थीं। उनके लिए भोजन फेंकना, बर्तन खाली छोड़ना या अन्न की अवहेलना करना पाप के समान था। खाली बर्तन उन्हें यह याद दिलाते थे कि अन्न का सम्मान नहीं हो रहा। इसलिए वे चाहती थीं कि कम से कम प्रतीकात्मक रूप से ही सही, बर्तन भरे रहें।

लक्ष्मी जी का संबंध भी इसी सोच से जुड़ा है। आम तौर पर लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा में लक्ष्मी का अर्थ बहुत व्यापक है। लक्ष्मी समृद्धि, व्यवस्था, संतुलन और सुख का प्रतीक हैं। जहां अन्न है, संतोष है और अनुशासन है, वहां लक्ष्मी का वास माना गया है। नए साल की पहली सुबह खाली बर्तन देखना दादी-नानी के अनुसार लक्ष्मी के अभाव का संकेत था, क्योंकि यह अन्न और व्यवस्था की कमी को दर्शाता था। इसी कारण पुराने समय में यह नियम था कि रात को बर्तन धोने के बाद भी उन्हें पूरी तरह खाली न छोड़ा जाए। कहीं थोड़ा सा चावल, कहीं दाल, कहीं दूध या पानी रख दिया जाता था। यह कोई बड़ा धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि एक छोटी-सी आदत थी जो पूरे घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखती थी। सुबह उठते ही भरे बर्तन देखने से मन में यह भाव आता था कि घर में कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी यह परंपरा महत्वपूर्ण मानी जाती है। रसोईघर को घर की ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। यहां से केवल भोजन नहीं, बल्कि पूरे परिवार की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा निकलती है। अगर रसोई में अव्यवस्था, गंदगी और खालीपन हो, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। खाली बर्तन उसी नकारात्मकता का प्रतीक बन जाते हैं। इसके विपरीत, साफ रसोई और भरे बर्तन समृद्धि, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देते हैं।

दादी-नानी के समय में “पॉजिटिव एनर्जी” या “वाइब्स” जैसे शब्द प्रचलन में नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहार इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था। वे जानती थीं कि घर का वातावरण इंसान के स्वभाव और भाग्य दोनों को प्रभावित करता है। खाली बर्तन देखने वाला व्यक्ति अनजाने में ही चिंता और असुरक्षा महसूस कर सकता है, जबकि भरे बर्तन देखने से मन में भरोसा और संतोष पैदा होता है।

यह परंपरा सामाजिक दृष्टि से भी बहुत व्यावहारिक थी। पुराने समय में परिवार बड़े होते थे और संसाधन सीमित। ऐसे में अनुशासन और व्यवस्था बहुत जरूरी थी। खाली बर्तन न रखने की आदत लोगों को भोजन की कद्र करना सिखाती थी। यह याद दिलाती थी कि अन्न आसानी से नहीं मिलता और उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नए साल की सुबह यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि वह पूरे वर्ष के लिए एक उदाहरण बन जाता था।

आधुनिक जीवन में हम अक्सर इन बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह परंपरा डर पर नहीं, बल्कि सोच पर आधारित थी। यह हमें सिखाती है कि जीवन को अभाव के नजरिए से नहीं, बल्कि पूर्णता के भाव से देखना चाहिए। जब हम अपने आसपास भरे हुए बर्तन, सजा हुआ घर और व्यवस्थित रसोई देखते हैं, तो हमारा मन भी उसी व्यवस्था को अपनाने लगता है। नए साल की पहली सुबह खाली बर्तन न रखने की सीख हमें कृतज्ञता का भाव भी सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अन्न है, घर है और परिवार है। कृतज्ञ व्यक्ति ही वास्तव में समृद्ध होता है। दादी-नानी शायद इस भावना को शब्दों में न कहती हों, लेकिन उनके हर नियम के पीछे यही भाव छिपा होता था। आज के समय में, जब नया साल केक, पार्टी और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित हो गया है, तब ऐसी परंपराएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि नया साल केवल तारीख बदलने का नाम नहीं, बल्कि सोच और ऊर्जा को सही दिशा देने का अवसर है। खाली बर्तन न रखना उसी दिशा में उठाया गया एक छोटा-सा लेकिन अर्थपूर्ण कदम है।

अंत में, दादी-नानी की यह सीख हमें यह समझाती है कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती। समृद्धि आती है संतुलन से, सम्मान से और सोच से। बर्तन भरे रखना एक प्रतीक है – इस बात का कि हम जीवन को खालीपन से नहीं, बल्कि पूर्णता और आशा के भाव से देखते हैं। जब यह भाव मन में बस जाता है, तो नया साल ही नहीं, पूरा जीवन अधिक संतुलित, शांत और समृद्ध बन जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस : वाइब्रेंट कच्छ जिला स्तरीय कार्यक्रम

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया के करकमलों से गांधीधाम में वाइब्रेंट कच्छ जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ

- वाइब्रेंट कच्छ कार्यक्रम में कुल 334 एमएसएमई इकाइयों के साथ 8500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा की गरिमामय उपस्थिति
- हस्तकला आधारित रोजगार वाला कच्छ आज गुजरात में औद्योगिक विकास का केन्द्र : राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : कच्छ के गांधीधाम में शुक्रवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने वाइब्रेंट कच्छ जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। इस कार्यक्रम में कुल 334 एमएसएमई इकाइयों के साथ 8500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। गांधीधाम के डॉ. बाबासाहब आंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट कच्छ कार्यक्रम का शुभारंभ कराते हुए श्री मोढवाडिया ने कहा कि कच्छ की सत्वशील जनता ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं की पीड़ा झेलकर आज कच्छ को विकास का केन्द्र बनाया है। सरकार के विजन तथा कच्छियों की तेजस्वी शक्ति तथा सत्व से कच्छ औद्योगिक हब बना है। कच्छ इस बात का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से एक प्रदेश का किस प्रकार कायाकल्प हो सकता है। कच्छी जिस प्रकार चुनौतियों को स्वीकार करने वाली जनता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने कच्छ की चुनौतियों को अवसर में पलटकर कच्छ का अभूतपूर्व विकास किया है। एक समय पानी, रोजगार आदि मुद्दों से पीड़ित कच्छ आज अन्य राज्यों के लोगों को रोजगार दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार द्वारा विकास के रथ को आगे बढ़ाए जाने से कच्छ आज टूरिज्म, खेती तथा औद्योगिक विकास में अग्रसर बना है। कच्छ रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनने के साथ देश का 40 प्रतिशत कारगो हैंडल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कच्छ के इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट के पीसीबी के निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों के विकास का मुख्य केन्द्र बन सकता है। ऐसे में उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि वे इन क्षेत्रों में जुड़ें।

इस अवसर पर धोलेरा के विकास की चर्चा करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री ने जोड़ा की चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करना प्रधानमंत्री के विजन में है। कोरोना काल में गिनती के दिनों में वैक्सीन बनाने से लेकर लोगों को देने तक का कार्य करके भारत ने अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया था। आज भारत वैक्सीन हब बना है। उसी प्रकार सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट की चुनौतियों को स्वीकार कर उसके उत्पादन के लिए सज्ज हुआ भारत आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनकर दुनिया में अग्रसर बनेगा।

उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके लिए कच्छ में भरपूर पोटेंशियल होने के कारण भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले क्षेत्र में निवेश के लिए कच्छ में आकर संपत्ति सृजन करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय एआई, क्वॉण्टम टेक्नोलॉजी तथा बायोटेक्नोलॉजी का होने के कारण इन क्षेत्रों में विकास के लिए आधुनिक रिसर्च सेंटर, एक्सीलेंस लैब आदि का निर्माण कर गुजरात सज्ज बना है। उन्होंने जोड़ा कि कच्छ का गोल्डन पीरियड चल रहा है। उन्होंने टिकाऊ विकास की विभावना तथा पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ कच्छ में वर्ल्ड क्लास नर्सरी बनाने को कहा। कच्छ में ग्रीन कवर बढ़ाने के अभियान में उद्योगों से जुड़ने का भी उन्होंने अनुरोध किया।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा ने प्रसंगोचित संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली, तब से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी। आज जिला स्तर पर उसका आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने कच्छ जिला प्रशासन तथा कच्छ के उद्यमियों को अभिनंदन दिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास को आंदोलन बनाकर भूकंप की पीड़ा के साथ पानी, बेरोजगारी की स्थिति में कच्छ को फिर से खड़ा किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन से कच्छ अविरत विकास साध रहा है। ढाँचागत सुविधाएँ बढ़ने, औद्योगिक विकास, टेक्नोलॉजी से युक्त बंदरगाहों का विकास होने से कच्छ में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है।

हस्तकला की कच्छी कारीगर श्री पाबीबेन को याद करते हुए श्री छांगा ने कहा कि एक समय हस्तकला तथा गृहोद्योग आधारित रोजगार देने वाला कच्छ हाल में गुजरात में उद्योगों का हब बनने जा रहा है। वाइब्रेंट के जरिये कच्छ में करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा है और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने नागरिकों तथा उद्योगपतियों से आर्थिक विकास के साथ ही नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए तथा सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए देश के विकास में सहभागी बनने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर कच्छ के सांसद श्री विनोदभाई चावडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दीर्घदृष्टिपूर्ण विजन से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी, जिसका लाभ कच्छ को मिलने से जिले में पोर्ट, मिनरल्स, केमिकल आदि क्षेत्रों में हजारों औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। आज कच्छ में रोजगार के विपुल अवसरों का सृजन होने से अन्य राज्यों के लोग यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। इसे कच्छियों के लिए गौरव की बात बताते हुए श्री चावडा ने जोड़ा कि कच्छ गुजरात का एक मात्र जिला है, जिसे रण (रेगिस्तान), समुद्र तथा पर्वत का त्रिवेणी संगम मिला है। मुख्यमंत्री के अविरत प्रयासों से आज कच्छ कृषि, उद्योग एवं टूरिज्म क्षेत्रों में अग्रसर बना है। उन्होंने युवा उद्यमियों तथा निवेशकों से प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल के विजन को सार्थक कर वाइब्रेंट कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। दीनदयाल पोर्ट के चेयरमैन श्री एस. के. सिंह ने कहा कि विकसित भारत के विजन में गुजरात राज्य तथा उसमें भी कच्छ जिला विशेष योगदान देगा। कच्छ की भौगोलिक स्थिति के कारण सभी प्रकार की कनेक्टिविटी उपलब्ध होने से निवेशक कच्छ के विकास में सहभागी होने को उत्सुक हैं। विकसित भारत के विजन में कच्छ में पोर्ट-मैरीटाइम सेक्टर का योगदान उल्लेखनीय रहेगा। उन्होंने जोड़ा कि कंडला पोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन तथा शिप बिल्डिंग क्षेत्र में लीड कर रहा है। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि भविष्य में जब इन दोनों क्षेत्रों का विकास होगा, तब वे कच्छ में ग्रीन हाइड्रोजन पार्क में जुड़ें।

इस अवसर पर कच्छ जिला कलेक्टर श्री आनंद पटेल ने कहा कि विकसित भारत का सपना साकार करने की पहल में बीज के रूप में बोया गया वाइब्रेंट गुजरात आज वटवृक्ष बना है। जिला स्तरीय वाइब्रेंट कार्यक्रम के आयोजन तथा साथ ही वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से एक समय का कच्छ आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बना है।

गांधीधाम चैम्बर्स के अध्यक्ष श्री महेशभाई पुंज ने प्रसंगोचित संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के विकास के विजन से कच्छ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, पोर्ट्स, केमिकल एंड मिनरल्स तथा टूरिज्म सहित महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अग्रसर बन रहा है। विकास के साथ कच्छ में मिले महत्वपूर्ण अवसरों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

डी. पी. वर्ल्ड के निदेशक श्री पराग कोचर ने ब्लू इकोनॉमी के महत्व के बारे में बताया और कच्छ में पोर्ट के विकास की अपार संभावनाएँ होने का उल्लेख करते हुए भारत-मार्ट के बारे में जानकारी दी।

किरी इंडस्ट्रीज के मनीष किरी ने कहा कि कच्छ गुजरात का आर्थिक पावर हाउस बन रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल स्ट्रक्चर, सी वॉटर, एग्रीकल्चर, एडवांस मरीन केमिकल मिनरल्स इंडस्ट्री के विकास से कच्छ की भूमि निवेशकों के लिए इंडस्ट्रियल लैंड बनकर उभरी है।

कच्छ मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री तेजाभाई कानगड ने कार्यक्रम के अंत में आभार ज्ञापन किया।

वाइब्रेंट कच्छ जिला कार्यक्रम में गांधीधाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इवेंट पार्टनर के रूप में, जबकि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट वेन्यू पार्टनर के रूप में जुड़ा। इसके अलावा फोकिया और कच्छ मैनेजमेंट एसोसिएशन नॉलेज पार्टनर के रूप में सहभागी हुए।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जनकसिंह जाडेजा, विधायक सर्वश्री केशूभाई पटेल, मालतीबेन महेश्वरी, प्रद्युम्नसिंह जाडेजा, अनिरुद्धभाई दवे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमाबेन आचार्य, अग्रणी श्री देवजीभाई वरचंद, श्री धवलभाई आचार्य, पूर्व कच्छ एसपी श्री सागर बागमार, गांधीधाम महानगर पालिका आयुक्त श्री मनीष गुरवानी, जीआरआईटी की जॉइंट सीईओ श्री स्तुति चारण, एआरएम श्री आशिष धानिया, संयुक्त उद्योग आयुक्त श्री कनक डेर सहित बड़ी संख्या में उद्योगकार तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा वलसाड एवं हिसार के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर चलने वाली वलसाड–हिसार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 04728 वलसाड–हिसार स्पेशल को 29 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04727 हिसार–वलसाड स्पेशल को 28 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 04728 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 04 जनवरी, 2026 से सभी PRS काउंटरों तथा IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ट्रेनों के ठहराव समय तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

उत्तरायण/मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा जनसमान्य से पटरियों के ऊपर लगे हाई वोल्टेज बिजली के तारों से दूर रहने की अपील

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के सभी खंडों में रेलवे लाइन के ऊपर 25,000 वोल्ट (25 kV) की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) हाई वोल्टेज तारें लगी हुई हैं। यह अत्यंत जानलेवा हैं। यह देखा गया है कि उत्तरायण/मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंग उड़ाते समय पतंग की डोर (मांझा) इन हाई वोल्टेज तारों में उलझ जाती है। ऐसे मामलों में रेलवे कर्मचारी जब ट्रैक पर कार्य करते हैं, तो इन धागों के संपर्क में आने से गंभीर विद्युत झटके का खतरा बना रहता है, जिससे जान को भी नुकसान हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, कई बार आम नागरिक भी रेलवे ट्रैक के समीप पतंग उड़ाते हैं तथा ओवरहेड तारों में फंसी पतंग को निकालने का प्रयास करते हैं, जो अत्यंत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है।

रेल प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं सतर्क रहें तथा दूसरों को भी अधिक से अधिक जागरूक करें।

अहमदाबाद मंडल ने जनसामान्य के लिए चलाया सुरक्षा जागरूकता अभियान

उत्तरायण पर्व के दौरान रेलवे ट्रैक के आसपास एवं ऊपर से गुजरने वाली 25,000 वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों से गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जनहित में रेलवे प्रशासन द्वारा आम नागरिकों को सुरक्षा संबंधी परामर्श (काउंसलिंग) दी जा रही है तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा हेतु कृपया निम्नलिखित सावधानियां अवश्य अपनाएं:

- रेलवे ट्रैक, ब्रिज, स्टेशन, पोल एवं ओवरहेड तारों से दूर पतंग उड़ाएं।
- रेलवे क्षेत्र में गिरी या फंसी हुई पतंग अथवा मांझा उठाने का प्रयास न करें।
- बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उन्हें रेलवे क्षेत्र से दूर रखें।

सुरक्षित रहें — जिम्मेदारी के साथ उत्तरायण मनाएं।

एमएसएमई निर्यातकों के लिए 7,295 करोड़ का पैकेज घोषित सस्ता कर्ज और गारंटी से मिलेगी वैश्विक बाजार में मजबूती

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, बढ़ती लागत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 7,295 करोड़ रुपये का व्यापक एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेज घोषित किया। इस पैकेज का सीधा लाभ देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई निर्यातकों को मिलेगा, जिन्हें लंबे समय से सस्ते कर्ज, ब्याज दरों में राहत और बिना अतिरिक्त गारंटी के वित्तीय सहायता की जरूरत थी। सरकार का मानना है कि इस पहल से निर्यातकों की वित्तीय मुश्किलें कम होंगी, उनकी कार्यशील पूंजी मजबूत होगी और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

सरकार ने इस पैकेज को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा है, ताकि निर्यात से जुड़े अलग-अलग वित्तीय पहलुओं को कवर किया जा सके। पहले हिस्से में ब्याज सहायता योजना के तहत 5,181 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पात्र एमएसएमई निर्यातकों को प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट पर अधिकतम 2.75 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि निर्यात से पहले कच्चा माल खरीदने, उत्पादन करने और निर्यात के बाद भुगतान प्राप्त होने तक की अवधि में लिए गए कर्ज पर ब्याज का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। सरकार ने प्रति फर्म सालाना लाभ की सीमा 50 लाख रुपये तय की है, जिससे अधिक से अधिक छोटे और मध्यम निर्यातकों तक इसका फायदा पहुंच सके।

पैकेज का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा कोलेटरल सपोर्ट यानी क्रेडिट गारंटी से जुड़ा है, जिसके लिए 2,114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत निर्यात से जुड़े वर्किंग कैपिटल लोन पर सरकार की ओर से गारंटी दी जाएगी। प्रत्येक फर्म को अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इससे उन निर्यातकों को खास राहत मिलेगी, जिनके पास अतिरिक्त संपत्ति गिरवी रखने के लिए नहीं होती, लेकिन उनके पास ऑर्डर और बाजार की संभावनाएं होती हैं। इस व्यवस्था से बैंक और वित्तीय संस्थान भी अधिक आत्मविश्वास के साथ एमएसएमई निर्यातकों को कर्ज दे सकेंगे।

सरकार के अनुसार, यह पैकेज 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 2025-31' का दूसरा बड़ा स्तंभ है। इससे पहले इस मिशन के तहत 31 दिसंबर 2025 को 4,531 करोड़ रुपये का 'मार्केट एक्सेस सपोर्ट' पैकेज लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को नए विदेशी बाजारों तक पहुंच दिलाना, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी बढ़ाना और ब्रांड इंडिया को मजबूत करना था। अब ब्याज सहायता और कोलेटरल गारंटी के जरिए निर्यातकों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने पर फोकस किया गया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के मुताबिक, यह सुविधा केवल चयनित 'पॉजिटिव लिस्ट' के उत्पादों पर लागू होगी। इसमें रक्षा से जुड़े उत्पाद, SCOMET श्रेणी के आइटम यानी विशेष रसायन, जीव, उपकरण और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिनका निर्यात रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने से न केवल विदेशी मुद्रा आय बढ़ेगी, बल्कि उच्च तकनीक और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड परिचालन एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन

अहमदाबाद मंडल ने दिसंबर 2025 में माल लोडिंग में भारतीय रेलवे में 7वां स्थान प्राप्त किया, दिसंबर 2025 में 5 मिलियन टन से अधिक रिकॉर्ड लोडिंग की एवं लगभग 885 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने दिसंबर 2025 में परिचालन और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए माल ढुलाई, आय अर्जन तथा यात्री सेवाओं में अब तक के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। यह उपलब्धि मंडल की सतत योजना, परिचालन दक्षता, व्यवसाय विकास और कर्मचारी समर्पण का प्रतिफल है।

- दिसंबर 2025 में मंडल ने अब तक का सर्वाधिक औसत दैनिक माल लोडिंग 3,224.74 वैगन दर्ज किया, जो नवंबर 2024 में प्राप्त 3094.84 वैगन के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। मात्रा के लिहाज से भी मंडल ने 5.03 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल लोडिंग हासिल किया, जो पूर्व के 4.81 मिलियन टन के रिकॉर्ड से अधिक है।
- क्षेत्रवार प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। गांधीधाम क्षेत्र ने 2,462.97 वैगन प्रतिदिन के औसत के साथ अब तक की सर्वाधिक लोडिंग दर्ज की, जबकि अहमदाबाद क्षेत्र ने 761.77 वैगन प्रतिदिन का प्रदर्शन किया। गांधीधाम एरिया से अब तक के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल नमक के वैगन लोड किए गए दिसंबर 2025 में 4,797 वैगन, जो जुलाई 2025 के पिछले बेस्ट 4,522 वैगन से ज़्यादा हैं।

- वस्तुवार ढुलाई में सभी प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई। नमक की ढुलाई 373.84 वैगन प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची, जो मंडल के इतिहास में सर्वाधिक है। इसके अलावा POL, उर्वरक, कोयला, कंटेनर, ऑटोमोबाइल एवं अन्य विविध वस्तुओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- ट्रेन संचालन के क्षेत्र में मंडल ने 2,319 क्रैक ट्रेनें चलाईं, 86 लॉन्ग-हॉल ट्रेनों का परिचालन किया तथा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालनता 94.32% रही।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने दिसंबर 2025 के दौरान दिसंबर 2024 की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज करते हुए माल, यात्री राजस्व, टिकट जांच, गैर-किराया आय तथा व्यवसाय विकास पहलों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। दिसंबर 2025 में मंडल ने 884.89 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया, जबकि दिसंबर 2024 में यह 702.35 करोड़ था। माल राजस्व 536.02 करोड़ से बढ़कर 701.39 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक माल प्रदर्शन है तथा निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है।

- यात्री राजस्व 167.00 करोड़ रहा, जबकि टिकट जांच से आय 2.10 करोड़ दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान मंडल ने 35.77 लाख यात्रियों का परिवहन किया।
- बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) के केंद्रित प्रयासों से कई वस्तुओं में अब तक की सर्वाधिक आय दर्ज की गई, जिसमें फर्टिलाइजर (240.97 करोड़), कंटेनर ट्रैफिक (211.45 करोड़) तथा नमक (114.04 करोड़) शामिल हैं। गांधीधाम, मोथाला, शिरवा, सनोसरा एवं सामाखियाली जैसे माल टर्मिनलों ने भी अब तक की सर्वाधिक कमाई दर्ज की।
- 27 दिसंबर 2025 को 26.87 करोड़ का एकदिवसीय माल राजस्व वित्तीय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रहा। अहमदाबाद मंडल ने दिसंबर 2025 में माल लोडिंग में भारतीय रेलवे में 7वां स्थान प्राप्त किया।
- पार्सल, लीजिंग एवं गैर-किराया राजस्व क्षेत्रों में ई-नीलामी के माध्यम से कई परिसंपत्तियों का आवंटन किया गया, जिससे अनुबंध अवधि में 23.55 करोड़ की आय प्राप्त होगी। दिसंबर 2025 तक गैर-किराया आय 10.84 करोड़ रही, जो मंडल के इतिहास में सर्वाधिक है, और इसके साथ ही मंडल ने भारतीय रेल में 4वां स्थान प्राप्त किया।
- यात्री-केंद्रित पहलों के तहत कुल 41 विशेष ट्रेन फेरों का संचालन किया गया।
- यात्रियों की सुविधा के लिए कलोल स्टेशन पर 4 जोड़ी प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया।
- टिकट जांच अभियानों को सुदृढ़ कर बिना टिकट/अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण किया गया।
- डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देकर यात्रियों को सरल एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराई गई।
- कैटरिंग इकाइयों, OSOP स्टॉलों, पे-एंड-यूज़ शौचालयों, पार्किंग अनुबंधों एवं विज्ञापन पहलों के माध्यम से राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया।

पश्चिम रेलवे का ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच 03/04 जनवरी, 2026 को मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। ब्रिज नंबर 5 के री-गर्डरिंग कार्य हेतु ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर 13 घंटे का मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक शनिवार/रविवार, 03/04 जनवरी, 2026 को 23:00 बजे से 12:00 बजे तक रहेगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट के बीच अप स्लो लाइन की सभी ट्रेनें अप फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। इसी प्रकार, चर्चगेट और माहिम स्टेशनों के बीच डाउन स्लो लाइन की ट्रेनें डाउन फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें महालक्ष्मी, प्रभादेवी एवं माटुंगा रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी तथा प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण लोअर परेल और माहिम स्टेशनों पर भी ठहराव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी तथा चर्चगेट जाने वाली कुछ ट्रेनों को बांद्रा/दादर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट अथवा रिवर्स किया जाएगा। उपरोक्त ब्लॉक के अतिरिक्त, प्रभादेवी स्थित आरओबी को हटाने के कार्य हेतु डाउन स्लो लाइन पर 23:30 बजे से 07:00 बजे तक 07:30 घंटे का एक और मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान यात्रियों को बांद्रा/दादर से माहिम, माटुंगा रोड, प्रभादेवी, लोअर परेल एवं महालक्ष्मी स्टेशनों तक ऑपोज़िट दिशा में यात्रा करने की अनुमति होगी। उदाहरणार्थ, चर्चगेट आदि स्टेशनों से महालक्ष्मी, लोअर परेल एवं प्रभादेवी जाने वाले यात्री दादर स्टेशन पर उतरकर उसी टिकट पर ऑपोज़िट दिशा अर्थात अप स्लो लाइन से यात्रा कर इन स्टेशनों तक जा सकते हैं। इसी प्रकार, चर्चगेट आदि से माटुंगा रोड एवं माहिम जाने वाले यात्री बांद्रा स्टेशन पर उतरकर उसी टिकट पर ऑपोज़िट दिशा अर्थात अप स्लो लाइन से यात्रा कर सकते हैं। निरस्त की गई ट्रेनों की सूची अनुलग्नक–I में तथा आंशिक रूप से समाप्त/वापस चलने वाली (शॉर्ट टर्मिनेटेड/रिवर्स) ट्रेनों की सूची अनुलग्नक–II में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्टेशन मास्टरों के पास भी उपलब्ध है।

सड़क हादसों में जीजा-साले समेत चार की मौत, एक ही दिन में दुर्घटनाओं से दहला सीतापुर

(जीएनएस)। सीतापुर। शुक्रवार का दिन जिले के लिए बेहद मनहूस साबित हुआ, जब अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों ने पूरे सीतापुर को शोक में डुबो दिया। एक ही दिन में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भाई-बहन समेत कई अन्य गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इन हादसों ने न सिर्फ परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि जिले में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। शाम के समय मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के मिश्रिख-सिधौली मार्ग पर रूपपुर पुलिया के पास हुए हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बाइक से जा रहे रामसेवक (19) निवासी मोहम्मदनगर और उनके साले विपिन (18) निवासी हाजीपुर को एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक हवा में उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सीएचसी मिश्रिख ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

दूसरी दर्दनाक घटना बहराइच मार्ग पर शिवपुरी पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां 34 वर्षीय गायत्री वर्मा की जान चली गई। गायत्री अपने पति संदीप वर्मा के साथ बाइक से मायके से लौट रही थीं। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे

एक तेज रफ्तार वाहन से बचने के प्रयास में बाइक असंतुलित हो गई। गायत्री सड़क पर गिर पड़ीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनन-फानन में उन्हें सीएचसी रेउसा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने एक खुशहाल परिवार की खुशियां छीन लीं। पति का रो-रोकर बुरा हाल है और बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया।

तीसरी घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के नरही रामपुर गांव के बाहर हुई, जहां गन्ना तौलकर लौट रहे किसान मनोज की ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। खेत-खलिहान से जुड़े लोग जब तक कुछ कर पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

इसी दिन थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के रन्नुपुर गांव के पास एक और हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार भाई-बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। मंजीत और उनकी बहन अपर्णा किसी परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। परिजन अस्पतालों के चक्कर काटते हुए दुआ कर रहे हैं कि दोनों की जान बच जाए। एक ही दिन में हुए इन सिलसिलेवार हादसों ने सीतापुर जिले को गहरे सदमे में डाल दिया है। हर हादसे के पीछे तेज रफ्तार, लापरवाही और सड़क सुरक्षा के प्रति उदासीनता की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और सड़कों पर निगरानी बढ़ाई जाए, तो ऐसे हादसों पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है। फिलहाल जिले में हर तरफ मातम पसरा है और चार परिवार अपनों को खोने का दर्द झेल रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के ड्राइवर व हेल्पर स्तरीय उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग के रूप में नागरिकों की सुरक्षित सवारी और समय पालन का सेवा दायित्व बस के सारथी के सिर है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- राज्य की आधुनिक परिवहन व्यवस्था के प्रहरी बस चालक हैं
- प्रधानमंत्री ने छोटे से छोटे व्यक्ति तक सड़क-मार्ग, बिजली-पानी, स्वास्थ्य सेवा, बस सेवा जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने वाला विकास सुनिश्चित किया है
- किसी भी स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बस के सारथी की है

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

- हाईवे लोड के साथ यातायात बोझ तथा प्रदूषण घटाने का उद्देश्य, 2027 तक एसटी बस में दैनिक यात्रा करने वाले नागरिकों की संख्या 30 लाख तक पहुँचाने का लक्ष्य
- वर्ष के 365 दिन और 24 घण्टे जनसेवा के लिए कार्यरत रहने वाले गुजरात के कर्मयोगियों को सलाम
- आधुनिक एवं सुविधापूर्ण परिवहन व्यवस्था के लिए वर्ष 2025 में 1714 नई बसें तथा 27 नए बस अड्डे नागरिकों की सेवा में समर्पित
- **पिछले 40 दिन में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में 45 हजार से अधिक उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए : परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीण माळी**
- **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जन सारथी ड्राइविंग स्कूल का शुभारंभ कराया**

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर में गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) के 3084 ड्राइवर तथा 1658 हेल्पर स्तरीय उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र प्रदान समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री पटेल ने कहा कि सड़क परिवहन निगम की बसों के ड्राइवर सुदूरवर्ती लोगों तक पहुँचते हैं। इसलिए ये बस चालक सुरक्षित सवारी के साथ समय पालन की बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर सरकार की इमेज का निर्माण करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने छोटे से छोटे व्यक्ति तक सड़क-मार्ग, बिजली-पानी, स्वास्थ्य सेवा, बस सेवा जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने वाला विकास सुनिश्चित किया है।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को राज्य की परिवहन व्यवस्था का प्रहरी बताया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य की परिवहन व्यवस्था का कायाकल्प किया और पुरानी-जर्जर बसों के स्थान पर एसी वॉल्वो जैसी बसें आज नागरिकों की सेवा में कार्यरत की गई हैं। राज्य सरकार ने परिवहन में जो आधुनिक सुविधाएँ मुहैया कराई हैं, उनका अच्छी तरह जतन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बस ड्राइवरों तथा हेल्परों के सिर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नागरिक एसटी बस ड्राइवरों के भरोसे निश्चिंत होकर यात्रा करते हैं। नागरिकों को समय पर गंतव्य स्थान तक पहुँचा कर सरकारी सेवा के साथ सामाजिक दायित्व निभाने का कार्य भी ये बस चालक करते हैं। यानी आम आदमी के जीवन से जुड़े बस चालकों का तन-मन से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में स्वस्थ रहकर, मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए ड्यूटी करना जरूरी है। इसके लिए पॉजिटिविटी से कार्यरत रहकर तथा जीवन में किसी भी स्थिति में बैलेंस बनाए रखने की सज्जता अर्जित करने का अनुरोध किया। श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नागरिक जीपीएस सहित आधुनिक सुविधाओं से सज्ज बसों की टैकिंग मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। फलस्वरूप जिन नागरिकों के लिए बसें चल रही हैं, उनकी समयबद्धता बनाए रखने का ध्यान भी बस चालकों को रखना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 में भारत को विकसित बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा है, उसमें स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों का राज्य की आधुनिक सुविधाओं से सज्ज बसों में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन सारथी ड्राइविंग स्कूल का शुभारंभ भी कराया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

राज्य के नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए 365 दिन और 24 घण्टे कार्यरत विभागों के कर्मचारियों को अभिनंदन देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि जब पूरी दुनिया त्योहार मनाती है, तब गुजरात के कुछ विभाग एक मिनट के लिए भी ठहरते नहीं हैं। श्री संघवी ने गर्व के साथ कहा कि अस्पतालों, पुलिस थानों, फायर ब्रिगेड तथा बिजली विभाग की तरह एसटी निगम के सभी कर्मचारियों की सेवाएँ 365 दिन और 24 घण्टे कार्यरत रहती हैं। रात-दिन, ठंड-गर्मी-बरसात देखे बिना काम करने वाले इन कर्मयोगियों की मेहनत ही गुजरात के सुशासन का सच्चा आधारस्तंभ है। श्री संघवी ने कर्मयोगियों की अविरत जन सेवा की ज्योत को मंच से दिल से सैल्यूट किया।

राज्य सरकार की कार्यक्षमता पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 3084 ड्राइवर तथा 1658 हेल्पर स्तरीय नवनियुक्त उम्मीदवारों की इस भर्ती प्रक्रिया द्वारा निगम को अधिक मजबूत बनाया गया है।

परिवहन क्षेत्र में भावी लक्ष्य निर्धारित करते हुए श्री संघवी ने कहा कि दैनिक अनुमानित 24 लाख यात्रियों को परिवहन सेवा प्रदान करने वाले एसटी निगम ने वर्ष 2025 तक 27 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। निगम ने दैनिक 27 लाख यात्रियों को सेवा देने के लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त किया है, जो गर्व की बात है। अब 2027 तक इस लक्ष्य को बढ़ाकर 30 लाख तक पहुँचाने का सरकार का संकल्प है। एक अध्ययन के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्त होगा, तो हाईवे लोड में तो कमी आएगी ही, साथ ही सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले फोर व्हीलरों की संख्या 25 हजार और टू व्हीलरों की संख्या लगभग 1 लाख घटेगी, जो प्रदूषण के साथ यातायात बोझ कम करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके अलावा, हाल में 9 लाख विद्यार्थी एसटी बसों का लाभ ले रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 10 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगर हम 10 लाख विद्यार्थियों तक पहुँच सकेंगे, तो और एक लाख परिवारों को सीधी सहायता मिलेगी और उन एक लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में हमारा योगदान जुड़ेगा।

वर्ष 2025 में एसटी विभाग द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि केवल एक वर्ष में 1714 नई बसें जनता की सेवा में जोड़ी गई हैं, जिनमें 962 सुपर एक्सप्रेस, 272 सेमी लग्जरी, 350 मिडी बसें, 30 वॉल्वो और 100 एसी बसें शामिल हैं। इसके साथ ही, यात्रियों की सुविधा के लिए 2025 में 27 नए बस अड्डों का लोकार्पण किया गया है तथा भविष्य के लिए 29 नए कार्यों का शिलान्यास भी कर दिया गया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से बसों में एवं बस अड्डों पर स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की अपील की।

इस अवसर पर परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीण माळी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व एवं उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में एसटी निगम ने अनेक नए आयाम हासिल किए हैं। आगामी समय में एसटी निगम 100 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ेगा, जिससे नागरिकों को खुल्ले पैसे लाने से मुक्ति मिलेगी। पिछले लगभग 40 दिनों में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में 45 हजार से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशभर में सरकारी नौकरी के लिए शुरू की गई 100 प्रतिशत पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत परीक्षा आयोजित कर अधिक से अधिक उम्मीदवारों को नौकरी मिले; उस प्रकार का आयोजन गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में हो रहा है। राज्य में गुड गवर्नेंस के फलस्वरूप सुदूरवर्ती युवा भी परीक्षा पास कर सरकारी सेवा में जुड़ रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के करकमलों से चार उम्मीदवारों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए तथा निगम द्वारा बनाए गए जन सारथी ड्राइविंग स्कूल का शुभारंभ किया गया।

प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ल ने सबका स्वागत करते हुए लगभग 4700 नए जुड़े कर्मयोगियों की पारदर्शी एवं मैरिट आधारित नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया की प्रशंसा की।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक सर्वश्री रीटाबेन पटेल, जयंतीभाई पटेल, बलराजसिंह चौहाण, अग्रणी श्री आशिषभाई दवे, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एम. नागराजन एवं बड़ी संख्या में नवनियुक्त उम्मीदवार उपस्थित रहे।

एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत दो प्रमुख उपाय शुरू किए गए: फियो ने निर्यात ऋण तक पहुंच में सुधार के कदम का स्वागत किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के तहत दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत का स्वागत किया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई निर्यात को मजबूत करना और किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में काफी सुधार करना है।

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा, "प्री- और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता और संपार्श्विक गारंटी तंत्र की शुरुआत एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली दो सबसे बड़ी चुनौतियों -ऋण की उच्च लागत और संपार्श्विक की कमी- को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। ये उपाय वैश्विक बाजारों में भारतीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बहुत बढ़ाएंगे।"

पहला उपाय पात्र ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। 2.75 प्रतिशत की आधार ब्याज सबवेंशन की घोषणा की गई है, जिसमें अधिसूचित कम प्रतिनिधित्व वाले या उभरते बाजारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है, जो परिचालन तत्परता के अधीन है। ब्याज सहायता हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) छह-अंकीय स्तर पर टैरिफ लाइनों की एक अधिसूचित सकारात्मक सूची के तहत निर्यात पर लागू होगी, जिसमें भारत की लगभग 75 प्रतिशत टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जो उच्च एमएसएमई भागीदारी वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) 50 लाख रुपए की निर्यातक-वार वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें दरों की समीक्षा मार्च और सितंबर में द्विवार्षिक रूप से की जाएगी। श्री रल्हन ने कहा कि डेटा-संचालित सकारात्मक सूची, जिसमें श्रम-गहन क्षेत्रों, एमएसएमई एकाग्रता और मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ वास्तविक निर्यातकों तक पहुंचे। रक्षा और स्कोमेट उत्पादों को शामिल करने से रणनीतिक और उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात को भी समर्थन मिलेगा। दूसरा उपाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के साथ साझेदारी में निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी सहायता प्रदान करता है। इस मैकेनिज्म के तहत, माइक्रो और छोटे निर्यातकों के लिए 85 प्रतिशत तक और मीडियम निर्यातकों के लिए 65 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज उपलब्ध होगी, जिसमें प्रति निर्यातक प्रति वित्त वर्ष अधिकतम 10 करोड़ रुपए का गारंटीड एक्सपोजर होगा।

फियो प्रमुख के अनुसार, "यह कोलैटरल गारंटी फ्रेमवर्क बैंकों को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड एमएसएमई को लोन देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और मौजूदा क्रेडिट गारंटी योजनाओं को पूरा करेगा। यह निर्यात करने वाले समुदाय, खासकर छोटे निर्यातकों की लंबे समय से चली आ रही मांग है, जिन्हें कोलैटरल की ज़रूरतों को पूरा करने में मुश्किल होती है।"

दोनों उपाय शुरू में पायलट बेसिस पर लागू किए जाएंगे, जिसमें फीडबैक और डेटा एनालिसिस के आधार पर लगातार मॉनिटरिंग और सुधार किए जाएंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और कोलैटरल गारंटी योजना के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 12 नवंबर 2025 को अप्रूव्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2030–31 की अवधि के लिए कुल आउटले 25,060 करोड़ रुपए है। यह मिशन वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है, और एमएसएमई पहली बार निर्यात करने वालों और लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस करता है।

इस मिशन में दो इंटीग्रेटेड सब-स्कीम शामिल हैं:

निर्यात प्रोत्साहन, जो किफायती और विविध ट्रेड फाइनेंस तक पहुंच पर फोकस करता है; और

निर्यात दिशा, जो मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस और ट्रेड इंटेलिजेंस जैसे नॉन-फाइनेंशियल इनेबलर्स को सपोर्ट करता है।

संक्षेप में, श्री रल्हन ने कहा कि फियो का मानना है कि ये उपाय निर्यात की लागत को कम करेंगे, फाइनेंस तक पहुंच का विस्तार करेंगे, निर्यात बाजारों में विविधता लाएंगे और भारत के निर्यात ब्रांड को मजबूत करेंगे। वे एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन में और गहराई से इंटीग्रेट करने और लगातार निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य की सभी नदियों के दोनों तटों की भूमि पर वन संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया

गुजरात की 185 नदियों के दोनों तटों की भूमि पर वन विभाग द्वारा 'वृक्ष पोषण अभियान' चलाया जाएगा : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

निर्णय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- वृक्ष पोषण से पहले भूमि का सीमांकन तथा जीआईएस मैपिंग कर कार्यक्षेत्र - भूमि की पहचान की जाएगी
- पहचानी गई भूमि का उपयोग केवल ग्रीन कवर-वृक्ष पोषण के लिए ही किया जाएगा
- ऐसी भूमि की सुरक्षा एवं रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग की रहेगी
- इस प्रकार की भूमि पर यदि अतिक्रमण होगा, तो उसे हटाने का अधिकार वन विभाग के पास रहेगा
- सामाजिक वनीकरण अंतर्गत शर्तों के अधीन संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा स्थान का चयन किया जाएगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की वैश्विक समस्या के बीच पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्ष पोषण एवं संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार के वर्ष 2023 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में वन एवं वृक्ष कवर राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.03 प्रतिशत है। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि इस ग्रीन कवर में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत गुजरात की कुल 185 नदियों के दोनों तटों की भूमि पर वन विभाग द्वारा 'वृक्ष पोषण अभियान' चलाया जाएगा। ग्रीन कवर बढ़ने से राज्य का वन क्षेत्र बढ़ेगा, जिससे वर्षा में वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन रोका जा सकेगा, साथ ही राज्य में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी।

वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने और विवरण देते हुए कहा कि राज्य में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए राज्य की सभी 185 नदियों के दोनों तटों के वन संरक्षण तथा संवर्धन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत वृक्ष पोषण के उपयोग हेतु भूमि का पहले सीमांकन तथा जीआईएस मैपिंग कर कार्यक्षेत्र निश्चित कर आवश्यकता वाली भूमि की पहचान की जाएगी। भूमि की स्थिति, विशेष रूप से सरकारी भूमि और अनुपयोगी सरकारी भूमि के रिकॉर्ड की जांच कर विकासोन्मुखी प्राथमिकताएं बनी रहें, इसके लिए इस भूमि का उपयोग केवल ग्रीन कवर-वृक्ष पोषण के लिए ही किया जाएगा। अन्य किसी उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि का उपयोग न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाली भूमि पर किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक या लाभकारी गतिविधि नहीं करनी होगी। ऐसी विवादास्पद भूमि पर केवल ग्रीन कवर-वृक्ष पोषण करने हेतु उपयोग की अनुमति दी जाती है। ऐसी भूमि की सुरक्षा, रखरखाव एवं संरक्षण की जिम्मेदारी वन एवं पर्यावरण विभाग/उसके अधीनस्थ कार्यालयों की होगी।

उन्होंने जोड़ा कि इस कार्यक्षेत्र अंतर्गत भूमि पर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण हो, तो उसे हटाने की कार्रवाई वन एवं पर्यावरण विभाग/उसके अधीनस्थ कार्यालयों को करनी होगी। यदि इस भूमि से बिजली लाइन या अन्य पाइपलाइन गुजरती है और उस संबंध में भूमि की स्थिति के अनुसार किसी अन्य संस्था-कार्यालय का अभिप्राय लेना आवश्यक लगे, तो संबंधित कार्यालय का अभिप्राय प्राप्त करना होगा।

उन्होंने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी विभाग द्वारा तथा वन क्षेत्रों में आने वाली सभी नदियों के रिवराइन फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट से संबंधित कार्य क्षेत्रीय वन विभागों को करने होंगे। उन्होंने जोड़ा कि इन संरक्षित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी नदियों के रिवराइन फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट से संबंधित कार्य सामाजिक वनीकरण विभागों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से स्थान का चयन कर, उनसे वह स्थान प्राप्त कर आगे का समग्र कामकाज शुरू किया जाएगा।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माळी ने कहा कि रिवराइन फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट के अंतर्गत नदियों के दोनों तटों पर 'वृक्ष पोषण अभियान' में नर्मदा, तापी, पूर्णा सहित दक्षिण गुजरात क्षेत्र की 17 नदियों, सौराष्ट्र क्षेत्र की 71 तथा कच्छ क्षेत्र की सबसे अधिक 97 नदियों को शामिल किया गया है। इस अभियान से नदियों के दोनों तटों की भूमि का कटाव रुकेगा और साथ ही भूमिगत जल स्तर भी और अधिक ऊंचा होगा।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए वन महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक वनों का निर्माण, नमो वड वन, तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशभर में शुरू किए गए मिशन लाइफ के अंतर्गत 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत विशेष अभियान चलाया गया है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में वृक्ष पोषण में उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नए अभियान के बाद गुजरात के ग्रीन कवर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सप्ताह के दौरान सोना-चांदी में परस्पर विरुद्ध चाल: सोना वायदा 2293 रुपये लुढ़का: चांदी वायदा में 12083 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 26 दिसंबर-2025 से 1 जनवरी-2026 के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 6812198.24 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 556441.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 6255663.85 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 34851 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 36676.96 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 443655.16 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 138574 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 140465 रुपये और नीचे में 134300 रुपये पर पहुंचकर, 138097 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2293 रुपये या 1.66 फीसदी की गिरावट के साथ 135804 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 115 रुपये या 0.1 फीसदी गिरकर 111936 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 42 रुपये या 0.3 फीसदी लुढ़ककर 13944 रुपये प्रति 1 ग्राम सप्ताह के अंत में बंद हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा 138565 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 140499 रुपये और नीचे में 134350 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 2316 रुपये या 1.68 फीसदी औंधकर 135771 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति 10 ग्राम 138800 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 140867 रुपये और नीचे में 131989 रुपये पर पहुंचकर, 138443 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 1746 रुपये या 1.26 फीसदी गिरकर 136697 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 224374 रुपये के भाव पर खूलकर, 254174 रुपये के उच्च और 222502 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 223790 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 12083 रुपये या 5.4 फीसदी के ऊछाल के साथ 235873 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 13688 रुपये या 6.1 फीसदी बढ़कर 237998 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 13697 रुपये या 6.11 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 238010 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 76529.16 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 120.05 रुपये या 10.24 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1292.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 3 रुपये या 0.98 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 308.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 9.15 रुपये या 3.18 फीसदी बढ़कर 297.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा जनवरी वायदा 40 पैसे या 0.22 फीसदी के सुधार के साथ सप्ताह के अंत में 182.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

- **क्रूड ऑयल वायदा 49 रुपये नरम: कमोडिटी वायदाओं में 556441.35 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 6255663.85 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 443655.16 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34851 पॉइंट के स्तर पर**

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 36117.09 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 5281 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 5314 रुपये के उच्च और 5170 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 49 रुपये या 0.93 फीसदी लुढ़ककर 5223 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा सप्ताह के अंत में 49 रुपये या 0.93 फीसदी गिरकर 5223 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 344 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 376.6 रुपये के उच्च और 317.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 339.1 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 9.6 रुपये या 2.83 फीसदी लुढ़ककर 329.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 9.4 रुपये या 2.77 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 329.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 960 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 51.7 रुपये या 5.41 फीसदी की तेजी के संग 1008.1 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 176923.68 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 266731.48 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 68287.78 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 3723.49 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 233.03 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 4284.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4125.77 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 31903.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 15753 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 49198 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 12588 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 180592 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 23896 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 13147 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 28310 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 54013 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18244 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25286 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 35200 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 36705 के उच्च और 34293 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 359 पॉइंट